केन्द्रीय बल उपलब्ध कराए गए हैं तथा वहां इन बलों की कितनी कम्पनियां तैनात की गई हैं ;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में केन्द्रीय बलों की अब तक कितनी कम्पनियां भेजी हैं ; और

(ङ) यदि ये कम्पनियां उस राज्य में अब तक नहीं भेजी गई हैं तो इन्हें वहां कब तक भेज दिया जाएगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमन ।

(ग) से (ङ) नक्सलवादी समस्या से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकारों को केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की कुछ कम्पनियां उपलब्ध कराई गई हैं। उनकी तैनाती के संबंध में निर्णय लेना राज्य सरकारों का काम है।

अन्य राज्यों में तैनात की गई मध्य प्रदेश पुलिस की वाहिनियां

1026. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के निर्देश पर अन्य राज्यों में तैनात की गई मध्य प्रदेश पुलिस की वाहिनियों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है और ये वहां कब से तैनात हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इन वाहिनियों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया है; यदि हां, तो इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) किन-किन राज्यों में तैनात इन वाहिनियों के व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी है और प्रतिपूर्ति की धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस धनराशि की प्रतिपूर्ति कब तक कर दिए जाने की संभावना है ;

(ङ) क्या सरकार ने यह निदेश दिया है कि जिन राज्यों की वाहिनियां अन्य राज्यों में तैनात की जाएं उन्हें तिमाही 25 लाख रुपए की अग्रिम धनराशि अदा की जाए, यदि हां, तो क्या इस निदेश का पालन किया जा रहा है और यदि नहीं, तो यह निदेश किन-किन राज्यों में अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है ; और

(च) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने किसी राज्य से अपनी वाहिनियां हटा लेने का अनुरोध किया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :-

चंडीगढ़	–	1 एम० पी० एस० ए० एफ० बटालियन जुलाई-अगस्त, 1990 से तैनात।
जम्मू और कश्मीर	–	एम०पी०एस०ए०एफ० की चार कम्पनियां अप्रैल, 1988 से तैनात हैं।

इसके अतिरिक्त, एम०पी०एस०ए० एफ० की 2 बटालियनें (इंडिया रिजर्व) 1971 में उनके गठित होने के बाद से राज्य के बाहर तैनात है। इस समय, इन बटालियनों की तैनाती निम्न प्रकार है :-

असम	–	4 कम्पनियां
त्रिपुरा	–	1 बटालियन
लक्षद्वीप	–	2 कम्पनियां

(ख) जी हां, श्रीमन् । मध्य प्रदेश सरकार को सूचना दी गई है कि वर्तमान

अनुदेशों के अनुसार, केवल कुछ छूट प्राप्त राज्यों, जिनके बारे में प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है, के मामलों के अलावा, बल उधार लेने वाले राज्य द्वारा बल उधार देने वाले राज्य को प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ग) शून्य।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मार्च, 1989 में इस आशय के अनुदेश जारी किए गए थे कि सशस्त्र पुलिस बटालियनों पर होने वाले खर्चे को, बल उधार लेने वाले राज्य द्वारा तिमाही खर्चे के आधार पर, 25 लाख रु० तक प्रति तिमाही प्रति बटालियन की दर से प्रत्येक वर्ष जून, सितम्बर, और दिसम्बर के अंत में भुगतान किया जाएगा। इन अस्थाई भुगतानों को, बाद में, वर्ष के अन्त, मार्च में, पिछले 10 महीनों में हुए वास्तविक खर्चे के आधार और शेष दो महीनों के लिए अनमानित खर्चे के आधार पर, समायोजन किया जाएगा, जिसका अगले वर्ष अंतिम रूप से अगले वर्ष के व्यय के आंकड़ों में लेखा परीक्षा हुए आंकड़ों में समायोजन किया जाएगा। आशा की जाती है कि सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र इन अनुदेशों का पालन करेंगे। तथापि, यह ध्यान में आया है कि असम राज्य और संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ और लक्षद्वीप के प्रशासनों द्वारा उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार को भुगतान नहीं किया गया है।

(च) मध्य प्रदेश सरकार ने असम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तैनात बटालियनों को वापस बुलाने का अनुरोध किया है। तथापि, यह भारतीय आरक्षित (इंडिया रिजर्व) बटालियनें हैं तथा उनके प्रयोग करने के लिए केन्द्र सरकार को पूर्व अधिकार प्राप्त है।

जम्मू और कश्मीर में राकेट हमले के कारण हुई मौतें

1027. **श्री राम नरेश यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 24 जनवरी, 1992 को जम्मू और कश्मीर में राकेट हमले में कितने अधिकारी मारे गए थे; और

(ख) सरकार ने भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न होने देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) 24 जनवरी, 1991 को जम्मू एवं कश्मीर में हुए राकेट आक्रमण में किसी भी अधिकारी-गण के मृत्यु के समाचार नहीं मिले हैं। तथापि उसी दिन बम विस्फोट में एक कांस्टेबल की मृत्यु हुई और उसके परिणाम स्वरूप श्रीनगर में पुलिस महा-निदेशक के कार्यालय में आग लग गयी।

(ख) सरकार ने आतंकवादियों के ऊपर दबाव बढ़ा दिया है और सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। आसूचना कार्रवाई को और गहन कर दिया है।

मराठवाड़ा और विदर्भ के लिए विकास बोर्ड

1028. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या गृह मंत्री 24.7.1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 625 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मराठवाड़ा और विदर्भ के लिए विकास बोर्डों के स्थापित किए जाने के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार कोंकण क्षेत्र के लिए विकास